

शर्यहाश दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-28 अंक-22

22 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2013

मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

मूल्य : 1 रुपया

दिल्ली विधानसभा चुनाव : कुछ विचारणीय मुद्दे

4 दिसम्बर को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों के बारे में देश के लोगों का तजुर्बा है कि चुनावों से केवल सरकार व मंत्री बदलते हैं लेकिन नीतियां नहीं बदलती। सही है कि आज चुनाव भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी व पैसे का खेल बन गये हैं। जिसके चलते लोगों में राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ रही है। लेकिन जनवादी भावना, मजदूर वर्ग के सही चिंतन व ईमानदार लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो न चाहते हुए भी अपराधी, गुण्डे व भ्रष्ट तत्व आसानी से सत्ता पर काबिज होते रहेंगे।

अतः हमें जनता के दुख-दर्दों के निवारण के लिए मजदूर वर्ग की सही सच्ची क्रांतिकारी राजनीति का झण्डा बुलंद करना होगा। मतदाता समाज के मौजूदा हालात पर गहराई से सोच-विचार करें और मतदान से पहले इस बात पर गौर करें।

जिन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण की नीतियों को केन्द्र व राज्यों में सत्तासीन पार्टियों की सरकारें लागू कर रही हैं उनके चलते पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व बड़े-बड़े व्यापारियों की तिजोरियां तो भर गई हैं मगर आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इन नीतियों के चलते अब जहां एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर दस पूंजीपतियों में से चार भारतीय हैं, वहीं यह दुनिया के सबसे अधिक भूखे व गरीब लोगों का भी देश बन गया है। खाद्यानों से देश के भण्डार भरे हुए हैं और खुले में सड़ रहे हैं, लेकिन देश के 77 फीसदी लोग घोर गरीबी व भुखमरी की दलदल में धसे हुए हैं। दुनिया में सबसे अधिक गन्ना, चावल व गेहूं उपजाने वाले किसान व खेत मजदूर आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। पिछले दस वर्षों में लगभग सात लाख किसानों ने आत्महत्या की है।

कमरतोड़ महंगाई

आटा, दाल, चावल सहित सभी तरह के खाद्यानों सब्जियों व आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ केन्द्र में कांग्रेस सरकार ने डीजल, पेट्रोल के दामों को बढ़ाकर व खाद्यानों के वायदा कारोबार की इजाजत देकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है वहीं दिल्ली की शीला सरकार भी नए टैक्स थोपकर तथा बिजली-पानी, यात्रा भाड़े व दूध जैसी चीजों के दाम बढ़ा कर आम लोगों पर बोझ लाद रही है। बिजली की दरें बहुत ज्यादा हैं। बिजली के बाद अब पानी के पूर्ण निजीकरण की प्रक्रिया जारी है ऐसा करके पानी को भी व्यापार की वस्तु बनाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में बिजली-पानी के बिल दोगुने से भी ज्यादा हो गये हैं।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रतिवादी जन सैलाब में डूबा कलकत्ता महानगर



विशाल जुलूस कलकत्ता में उमड़ पड़े जन सैलाब का एक दृश्य

मानो इसी तरह के एक प्रतिवाद का इंतजार ही कर रही थी पश्चिम बंगाल की जनता। महंगाई, नारी-उत्पीड़न सहित लोगों की भयंकर दुर्दशा के प्रतिवाद में 12 नवम्बर को जन समुद्र के ज्वार में डूब गया कलकत्ता महानगर। पूरे राजपथ पर जन लहरों के रूप में जबरदस्त रोष फूट पड़ा था। जन जीवन को त्रस्त कर रही दुर्दशा के खिलाफ हजारों हजार लोगों ने आवाज बुलन्द की। असंख्य हाथों में मांगों के बैनर, फेस्टून लहरा रहे थे जिन

पर लिखा था महंगाई व जमाखोरी पर तुरन्त रोक लगाओ, नारी उत्पीड़न रोकने के लिए सरकार को तुरन्त उपयुक्त कदम उठाने होंगे, स्कूल स्तर पर यौन शिक्षा बंद करो, पास-फेल हटाना नहीं चलेगा, बिजली के बड़े हुए रेट वापस लो, इत्यादि। आसमान की तरफ मुट्ठी ताने लोग मांग कर रहे थे-प्रतिकार चाहिए। मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आगामी दिनों में हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत के स्तर पर आन्दोलन चलाने

की शपथ वातावरण में गूँज रही थी।

एक तरफ फसल कटाई के लिए पक कर तैयार खड़ी थी, ऊपर से रोजी-रोजगार की हजारों बाधाएं थी। विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा का समय बहुत करीब था। फिर भी पहाड़ से समुद्र तक-पूरे राज्य के हर जिले से एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के आह्वान पर 12 नवम्बर के महा प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 48 हजार से

(शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रतिवादी जन सैलाब...

(पृष्ठ 1 का शेष)

ज्यादा लोग जुटे थे। इसमें शामिल थे छात्र-नौजवानों, किसान-खेतमजदूरों, संगठित क्षेत्र के मजदूर-कर्मचारियों, बीड़ी मजदूरों, मोटर वैन चालकों, रोजाना काम करके पेट पालने वाले दिहाड़ी मजदूर, घरों में काम करने वाली परिचारिकाओं के झुण्ड के झुण्ड। इससे पहले तीन महीने से मांग पत्र पर हस्ताक्षर संग्रह का काम चल रहा था। इस दिन 42 लाख 772 हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन इस महा प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री के कार्यालय में सौंपा गया।

जुलूस ठीक डेढ़ बजे हेदुबा पार्क से शुरू हुआ। कॉलेज स्ट्रीट, बहुबाजार, सुबोध मल्लिक स्क्वेयर आदि चौराहों से और भी ज्यादा लोग जुलूस में शामिल होते गये। विशाल जुलूस की वजह से बहुत लोग रास्ते में फंस गये। लेकिन इस सामयिक असुविधा की जरा भी शिकायत उनके मन में नहीं थी। वे सोच रहे थे कि यह उनका ही तो जुलूस है। दक्षिण 24 परगना के एक राजमिस्त्री फूटपाथ पर खड़े थे। असुविधा हो रही है या नहीं यह पूछने पर बोले, '200 रुपये रोजाना दिहाड़ी पर काम करता हूँ जिससे घर का गुजारा चलता नहीं है। इस तरह के जुलूस तो और भी ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है।'

महाप्रदर्शन का नेतृत्व केन्द्रीय कमिटी सदस्य और पश्चिम बंगाल राज्य सचिव कॉमरेड सोमेन बसु के अलावा केन्द्रीय कमिटी सदस्यगण सर्वकॉमरेड देवप्रसाद सरकार, शंकर साहा, गोपाल कुण्डू, राज्य सचिवमण्डल सदस्यगण सर्वकॉमरेड तपन राय चौधरी, प्रशांत घटक, मानव बेरा कर रहे थे। सांसद तरुण मण्डल और विधायक तरुण नशकर भी शामिल थे।

दिल्ली चुनाव...

(पृष्ठ 1 का शेष)

रोजगार का बढ़ता संकट

लाखों नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। सरकारी भर्तियों पर रोक, हजारों पदों की समाप्ति जैसे कदम यह साफ कर देते हैं कि दिल्ली सरकार रोजगार के लिए कितनी गंभीर है। दिल्ली में कहीं भी नए उद्योग कारखाने नहीं लग रहे हैं। बचे-खुचे उद्योग-धंधे भी आर्थिक मंदी की चपेट में हैं। हर रोज कर्मचारियों की छटनी की खबरें आ रही हैं। केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों की कोई रोजगार नीति नहीं है मगर रोजगार कटौती की योजना जारी है।

शिक्षा व स्वास्थ्य भी छीना जा रहा है

इनका निजीकरण व व्यापारीकरण करने के चलते ये जन-सुविधाएं भी लोगों से दूर होती जा रही हैं। सैकड़ों-हजारों निजी स्कूल, कॉलेज व अस्पताल खुल गए हैं। जहाँ पर मोटी रकम देकर ही कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा पा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 17% लोग हर वर्ष इसलिए गरीबी व भुखमरी में धंसते जा रहे हैं क्योंकि वे इलाज के लिए ही अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं।

शिक्षा के बारे में कांग्रेस व भाजपा की नीतियां समान हैं। दिल्ली में शिक्षकों के 17 हजार पद खाली पड़े हैं। इस कारण भाजपा शासित नगर निगम के 218 स्कूल व कांग्रेस शासित दिल्ली सरकार के 70 स्कूल बंद पड़े हैं। उच्च शिक्षा का आत्म तो यह है कि दिल्ली से 12वीं पास करने वाले लगभग 75 हजार छात्रों को कालिजों में दाखिला नहीं मिलता। पिछले 15 वर्ष में दिल्ली सरकार ने एक भी कॉलेज नहीं खोला है। पढ़ाई के लिए छात्रों को बैंक कर्ज लेकर निजी कालिजों में कोर्स करने पड़े रहे हैं। शासक दोनों दल स्कूलों में यौन शिक्षा लागू करने पर आमामादा है जिनका उद्देश्य छात्रों का नैतिक पतन करना है।

सरकार आठवीं तक बेरोकटोक पास करने की नीति लागू कर रही है। जिस कारण नौवीं कक्षा का बच्चा पांचवीं कक्षा का सिलेबस तक नहीं पढ़ पाता है। नौवें इतनी कमजोर कर दी गई है कि वे उच्च शिक्षा पाने के लायक ही नहीं रहते। अभी दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को वैकल्पिक बनाना, कॉलेजों में सेमेस्टर

रानी रासमणि ऐवन्यु में जुलूस के प्रवेश करने के बाद हुई संक्षिप्त सभा को राज्य सचिव कॉमरेड सोमेन बसु ने सम्बोधित किया। विगत कई महीनों से चिलचिलाती धूप में, बारिश में भीगते हुए हर रास्ते के नुकड़ पर, स्टेशन, बस स्टैंड, हाट-बाजार, कारखानों के गेट पर हस्ताक्षर संग्रह करने के लिए जिन सब कार्यकर्ताओं-समर्थकों और राज्य के तमाम लोगों का जिन्होंने आगे आकर हस्ताक्षर करके आन्दोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया-उन सभी का अभिनन्दन करते हुए कॉमरेड सोमेन बसु ने कहा कि धान कटाई अपने चरम पर होने के बावजूद आज के जुलूस में इतने सारे लोगों के शामिल होने की घटना से ही जन जीवन की दुर्दशा के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ जनविश्लेष व आन्दोलनमुखी मानसिकता का साफ पता चलता है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर आदमी को खाना उपलब्ध हो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। फिर भी तृणमूल सरकार ने लोगों को जमाखोरों और कालाबाजारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सिर्फ आलू-प्याज ही नहीं, साग-सब्जियाँ, यहाँ तक कि चावल के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) बहुत दिनों से मांग करती आ रही है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं, खास तौर पर खाद्य पदार्थों के व्यापार सरकार अपने हाथ में ले। लेकिन जमाखोरों, कालाबाजारियों और आदतियों के पैसों से जो राजनैतिक पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं उनकी क्या मजाल कि वे इनके खिलाफ जाकर आम जनता के स्वार्थ की रक्षा करें। जिस तरह सीपीआई(एम) महंगाई को देख कर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी ठीक उसी तरह उसी रास्ते पर आज तृणमूल सरकार भी चल रही है। कॉमरेड बसु ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र पर भी

सरकार ने भयंकर हमला किया है। सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक पास-फेल हटा कर राज्य के 80 प्रतिशत छात्रों से असल में शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया जा रहा है। शराब के भारी बढ़ावे के साथ-साथ अश्लील सिनेमा, विज्ञापन, नग्नता का चौतरफा बोलबाला होता जा रहा है। नतीजतन नारी उत्पीड़न की घटनाएं इतने व्यापक रूप से बढ़ रही हैं। सर्वहारा के महान नेता, एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा निर्देशित रास्ते पर हम लगातार इन सब के विरुद्ध आन्दोलन संगठित करते जा रहे हैं। इससे पहले सीपीआई(एम) सरकार के फासीवादी क्रियाकलापों के खिलाफ राज्य भर में लोकतांत्रिक माहौल को बचाने की जरूरत से हमने तृणमूल कांग्रेस के साथ संयुक्त रूप से आन्दोलन किया था। विशेषकर सिंगूर-नंदीग्राम आन्दोलन को केन्द्र करके राज्य के लोग सीपीआई(एम) के विरोध में सड़कों पर उतर आये थे। आन्दोलन का वही रास्ता अपना कर ही तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई है। फिर भी आज वह ठीक सीपीआई(एम) की तरह ही जनता की दुर्दशा से मुँह मोड़ ले रही है, जुलूसों-हड़तालों पर निषेधाज्ञा जारी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 34 वर्षों तक सीपीआई(एम) ने हमारे आन्दोलनों पर बेइतहा हमले किये, 150 नेता-कार्यकर्ताओं का कत्ल कर डाला, जेलों में दूंस दिया। लेकिन एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) को आन्दोलन के रास्ते से डिगा नहीं पाये। तृणमूल कांग्रेस सरकार भी नहीं डिगा सकेगी। जन जीवन की दुर्दशा के खिलाफ लगातार आन्दोलन के हिस्से के तौर पर आने वाले तीन महीनों के कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए हर जिले के हर ब्लॉक में जनता को संगठित करने के काम में जुट जाने का उन्होंने आह्वान किया।

प्रणाली लागू करना व डिग्री कोर्स को चार वर्गीय बनाना, शिक्षा व्यवस्था व छात्रों के भविष्य पर नये आघात हैं।

सांस्कृतिक पतन को बढ़ावा

रेडियो, टी.वी., पत्र-पत्रिकाओं व इंटरनेट आदि माध्यमों से बड़े पैमाने पर अश्लीलता फैलायी जा रही है। छात्र-नौजवानों को गहरे सांस्कृतिक पतन की तरफ धकेला जा रहा है। सरकारें यदि चाहे तो इस पर रोक लगा सकती हैं मगर वे जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही हैं बल्कि वे नैतिक पतन बढ़ाने के लिए शराब व नशाखोरों को भी बढ़ावा दे रही हैं। सरकार ने लगभग हर रोज नई शराब की दूकानें खोली हैं। परिणाम यह है कि मां-बहनों-बेटियों पर हर रोज पाश्र्विक हमले बढ़ते जा रहे हैं।

महिलाओं पर अपराधों में भारी बढ़ोतरी

महिलाओं पर अपराधों के इस साल अक्टूबर तक 1330 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुने हैं। जबकि छेड़खानी के मामलों में चार गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली बच्चों व महिलाओं पर होने वाले अपराधों में देश में पहले नम्बर पर है।

दो तस्वीरें

दिल्ली की दो तस्वीरें हम देखते हैं। दिल्ली का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ चौड़ी सड़कें, फ्लाई ओवर, अंडरपास तथा बिजली की चकाचौंध है जिस पर करोड़ों-अरबों रुपया खर्च कर असल में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। मगर इसी दिल्ली की 70 फीसदी आबादी पीने के साफ पानी, बिजली की नियमित सप्लाई, गंदे पानी की निकासी, नालियाँ, सड़कों, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर व आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। दिल्ली की इस दुर्दशा के लिए विधानसभा में सत्तासीन कांग्रेस तथा नगर निगम की गद्दी पर बैठी भाजपा दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं। दिल्ली की राशन व्यवस्था को चौपट कर डालने, दिल्ली के उद्योगों को तहस-नहस करने, दिल्ली के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तक भी न दिलवाने व स्थाई कामों की जगह पर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही जनविरोधी भूमिका निभाई है।

नीतियों के मामले में आम आदमी पार्टी की कांग्रेस

व भाजपा से कोई मूलभूत भिन्नता नहीं है। उदारिकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी व उसके नेता केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे केवल इन नीतियों से उभर रही समस्याओं का व बिजली-पानी की बढ़ी दरों का सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। मूलतः यह विरोध उसी प्रकार का है जैसे कि भाजपा व अन्य पूंजीवादी पार्टियाँ करती हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को पूंजीपतियों व उनके मीडिया का भरपूर समर्थन है। कांग्रेस व भाजपा के कुशासन से त्रस्त लोगों के आक्रोश का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी राजनीति में करने के लिए हर रास्ता अपना रही है। उन्होंने सत्ता की राजनीति के लिए उस अन्ना आंदोलन की पीठ में भी छूरा घोंप दिया, जिस आंदोलन को देश के आम लोगों का भारी समर्थन था और जिसके दबाव में केन्द्र सरकार को संसद में प्रस्ताव पारित करके लोकपाल बिल लाने का देश से वादा करना पड़ा था। केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के नेता आंदोलन का रास्ता छोड़कर सत्तापाने की खातिर पूंजीपतियों के अनुकूल नीतियाँ रखते हुए अब चुनाव मैदान में आ गये हैं। आने वाला समय शीघ्र ही उनके चेहरे पर पड़े नाकाब को पूरी तरह हटा देगा और यह लोगों में साफ हो जायेगा कि आम आदमी पार्टी, दूसरी संसदीय पार्टियाँ कांग्रेस, भाजपा, सपा व बसपा से कोई मूलभूत भिन्नता नहीं रखती।

दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन

कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा सहित सभी संसदीय पार्टियाँ समाज को दुर्दशा में धकेलने के लिए जिम्मेदार हैं। केन्द्र व राज्य में सत्तासीन उनकी सरकारें पूंजीपति वर्ग की सेवा के लिए एक-दूसरे से होड़ कर रही हैं। इन पार्टियों ने लोगों को दुर्दशा को बढ़ाया है। भ्रष्टाचार किया है। जनता के पैसे और प्राकृतिक संपदा की लूट मचाई है। जनकल्याण के कार्यों पर खर्च करते समय इनकी सरकारें अपना खजाना खाली होने का रोना रोती हैं। मगर जनता पर अपना शनाप टैक्स थोप कर बटोरे गये सरकारी खजाने से अरबों-खरबों रुपये की विशाल दौलत वे हर वर्ष पूंजीपतियों को राहत पैकेजों के रूप में लुटा रही हैं।

पार्टियाँ अनेक मगर राजनीति केवल दो

याद रखें, वर्ग-विभाजित समाज में पार्टियाँ तो बहुत हो सकती हैं लेकिन राजनीति सिर्फ दो ही है। एक है

(शेष पृष्ठ 4 पर)

शहीद भगत सिंह पर पुस्तक के विमोचन के दौरान अश्लील गाने शहीदों का अपमान

एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा ने 11 नवम्बर को निम्नलिखित बयान जारी किया :

“ये बेहद खेद की बात है कि गत शनिवार को भगत सिंह की जेल डायरी के विमोचन की खातिर पटियाला के राजकीय महेन्द्र कॉलेज में हुए कार्यक्रम के दौरान अश्लील गाने पेश किये गये। महान शहीद के रिश्तेदार मि. युद्धविन्दर सिंह की उपस्थिति में यह सारा कार्यक्रम हुआ, न तो उनकी ओर से और न ही श्रोताओं की ओर से किसी ने इसका विरोध किया। हम इस बेहूदगी का कड़ा प्रतिवाद करते हैं और इस घटना में शामिल लोगों को सजा देने की मांग करते हैं। शहीद-ए-आजम भगत सिंह जो एक नास्तिक थे, उनकी पुस्तक के विमोचन समारोह में घोर साम्प्रदायिक व्यक्ति मि. नरेन्द्र मोदी को मि. संधु द्वारा आमन्त्रित किये जाने के प्रयास की भी हम कड़ी निन्दा करते हैं। शहीद भगत सिंह जो धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वासों, साम्प्रदायिक विचारों और रूढ़िवादिता के खिलाफ लड़े और जिन्होंने भारत की सरजमीन पर वैज्ञानिक समाजवाद का सपना देखा था, उनके ही एक रिश्तेदार द्वारा उनके तमाम संघर्षों को भूलकर भारत में साम्प्रदायिक राजनीति के सरगना और गुजरात साम्प्रदायिक दंगों के मुख्य आरोपी नरेन्द्र मोदी को समर्थन देने का प्रयास अत्यंत खेदजनक है।

कॉमरेड बी एस प्रतिभा कुमारी लाल सलाम

कर्नाटक में महिला आन्दोलन की अगुआ संगठक कॉमरेड बी एस प्रतिभा कुमारी के अचानक असामयिक निधन पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की कर्नाटक राज्य कमेट्री गहरा शोक प्रकट करती है। वे 46 वर्ष की थीं। वे ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की कर्नाटक राज्य अध्यक्षा और एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बैंगलोर जिला कमेट्री की सदस्य थीं। उन्होंने विभिन्न सफल जनआन्दोलनों में भी सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी।

कॉमरेड प्रतिभा कुमारी पोस्ट ग्रेजुएट थी और 19 वर्ष की अल्पायु में ही मार्क्सवाद और कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों के प्रति आकर्षित हुई थी। उन्होंने गरीब और शोषित लोगों के हितार्थ अपना जीवन समर्पित करने का फैसला लिया था। अपने 27 वर्षों की क्रान्तिकारी गतिविधियों के दौरान उन्होंने कर्नाटक के अनेक जिलों में ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की सक्रिय इकाइयाँ विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई थी।

वयवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री एस एस डोरेस्वामी, प्रसिद्ध लेखक और वकील श्रीमती हेमलता महिषी और अन्य कई गणमान्य लोगों ने कॉमरेड प्रतिभा कुमारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किये।



श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती और केन्द्रीय कमेट्री सदस्य व कर्नाटक राज्य कमेट्री सदस्य कॉमरेड के राधाकृष्ण भी उपस्थित थे। उनके सैकड़ों सहकर्मियों व प्रशासकों के सजल आँखों और रुंधे हुए गले से लग रहे नारों के बीच श्रीरामपुरम के हरिशचन्द्र घाट पर उनका अन्तिम संस्कार किया गया।

7 नवम्बर को बैंगलौर में एक स्मृति सभा आयोजित की गई जिसमें कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मुख्य वक्ता थे।



मांगों को लेकर हरियाणा में श्रमिकों ने प्रदर्शन किये, ज्ञापन सौंपा

बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, सस्ता राशन मुहैया कराने, सभी मजदूरों को 15 हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने, श्रम कानूनों की पालना करने, आंगनवाड़ी कर्मियों, आशा व मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 2500 रुपये मासिक पेन्शन देने, भवन निर्माण मजदूर-कारीगरों का पंजीकरण सरल करने व आर्थिक सहायता बढ़ाने, नई पेन्शन स्कीम वापस लेने व पुरानी पेन्शन स्कीम बहाल करने और 45 दिन के अन्दर यूनियन का पंजीकरण करने आदि मांगों को लेकर 8 नवम्बर को ऑल इण्डिया यू.टी.यू.सी. ने मजदूर मांग दिवस के रूप में मनाया। ऑल इण्डिया यू.टी.यू.सी. के बैनर तले जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गये। गुडगांव में प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष कॉमरेड श्रवण कुमार, सचिव कॉमरेड रामकुमार व सदस्य बलवान सिंह, निरंजन, श्यामसुन्दर आदि ने किया। रोहतक में संगठन के जिला अध्यक्ष कॉ. जिले सिंह, भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के जिला सचिव कॉ. जगदीश, आंगनवाड़ी कर्मियों की यूनियन की राज्य महासचिव पुष्पा दलाल आदि ने किया। भिवानी में जिला सचिव कॉ. धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने ज्ञापन दिया। सोनीपत में संगठन के राज्य सचिव कॉ. हरिप्रकाश के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। कैथल में कॉ. राजकुमार ने अगुआई की। नारनौल में एआईयूटीयूसी के कॉ. सुभाष के अलावा संयुक्त कर्मचारी मंच के प्रदेश सचिव सूबे सिंह भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के सीताराम आदि ने नेतृत्व किया। रेवाड़ी में कॉ. बलराम, आशा कार्यकर्ता प्रधान राजबाला, आंगनवाड़ी संगठन की प्रधान कृष्णा यादव मिड डे मील संगठन की प्रधान सरस्वती देवी आदि उपस्थित थे।



रोहतक। लघु सचिवालय पर प्रदर्शन में शामिल श्रमिक



रेवाड़ी। जिला स्तरीय प्रदर्शन में शामिल श्रमिक



सोनीपत। मजदूरों को वेतन को लेकर जगजगत् की आवाज देने के लिए उभरती नेताम।



कैथल। मांग दिवस पर एआईयूटीयूसी के प्रदर्शन में शामिल श्रमिक



नारनौल। महावीर चोक पर एआईयूटीयूसी के प्रदर्शन में शामिल श्रमिक

दिल्ली चुनाव ...

(पृष्ठ 2 का शेष)

पूँजीपति वर्ग के स्वार्थ सिद्धि की राजनीति, मुनाफाखोरी पर आधारित लूट को बरकरार रखने की राजनीति, संसद या विधानसभा में जाकर पूँजीपतियों के हित साधने की राजनीति, इस राजनीति को करने वालों के लिए पूँजीपतियों की तिजोरियों के मुँह खुले हुए हैं। पूँजीपतियों द्वारा संचालित मोडिया, पुलिस-प्रशासन का प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए चुनावों में ये जनहित की बातें और बड़े-बड़े वायदे करती हैं लेकिन सत्ता में जाकर सेवा पूँजीपति वर्ग की ही करती हैं। दूसरी राजनीति है मेहनतकश आवाज के हितों की रक्षा करने की राजनीति, मौजूदा शोषणमूलक व्यवस्था को क्रांति के जरिए उखाड़ फेंकने की राजनीति, विधानसभा में जाकर मेहनतकशों की आवाज को बुलंद करने की राजनीति। भारत में इस राजनीति की नुमाइंदगी करने वाली एकमात्र पार्टी है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट)। हालांकि समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किए बिना जन-समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। फिर भी इस मौजूदा व्यवस्था में भी अपनी जायज मांगें हासिल करने का एकमात्र रास्ता है जातिवाद, साम्प्रदायिकता व हर प्रकार की फूटपरस्त राजनीति को परास्त करते हुए व मेहनतकश जनता के सभी तबकों को शामिल कराते हुए जनवादी जनआंदोलन तेज करना।

एस.यू.सी.आई.(सी) हर मुद्दे पर संघर्षरत

पिछले वर्ष 14 मार्च को एस.यू.सी.आई.(सी) के नेतृत्व में देशभर के लाखों लोगों ने राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से मार्च किया व संसद पर विशाल प्रदर्शन किया। लोगों की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने के लिए 3 करोड़ 57 लाख लोगों का हस्ताक्षर युक्त मांगपत्र प्रधानमंत्री को सौंपा। दिल्ली में हमारी पार्टी बढ़ती महंगाई, बिजली-पानी की बढ़ती दरों व उनके

निजीकरण के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा व रोजगार के सवाल पर, मजदूरों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि आदि मामलों पर निरन्तर आंदोलन चला रही है। बुराड़ी, जहाँगीरपुरी, मुकुन्दपुर, आदि क्षेत्रों में भी राशन, सफाई व अन्य मुद्दों पर हमारी पार्टी व जन संगठनों ने छात्रों, नौजवानों, महिलाओं व मजदूर-कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक के बाद एक जनआंदोलन किये हैं। हमारी पार्टी आजादी आंदोलन के क्रांतिकारी शहीद भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशाफाक उल्ला खां, प्रीतिलता, व महानायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस के उच्च बलिदान, संघर्ष व सामाजिक उत्तरदायित्व बोध से मिलने वाली प्रेरणा को ले जाने के साथ-साथ ही महात्मा ज्योतिराव फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद व शरत चंद्र आदि की मूल्यवान सीखों को समाज में ले जाकर सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन को भी विकसित करने का प्रयास कर रही है।

हमारे लिए चुनाव ई जनहित में आंदोलन को आगे बढ़ाने का माध्यम

इसी तात्पर्य के साथ हमारी पार्टी ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और आंदोलन में जांचे परखे व तपे हुए कॉ. मैनेजर चौरसिया को उम्मीवार बनाया है। कॉ. मैनेजर चौरसिया ने जन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह निश्चित है कि जनता की लड़ाई को चुनाव के बाद भी वे जारी रखेंगे। लिहाजा उनकी जीत वास्तव में ही आपकी जीत होगी। जनता की जीत होगी। आन्दोलन की जीत होगी। मतदाता साथियों हमारी अपील है कि आप भ्रष्ट, जनविरोधी, साम्प्रदायिक, जातिवादी व फूटपरस्त राजनीति को परास्त करें। कांग्रेस, भाजपा सहित पूँजीपति वर्ग की सेवादार पार्टियों को शिकस्त दें और जनपक्ष की क्रांतिकारी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एस.यू.सी.आई.(सी)के उम्मीवार को अपना वोट व तन-मन-धन से समर्थन देकर कामयाब बनायें।

विधान सभा चुनावों में

भारत की एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी एसयूसीआई(सी) के प्रत्याशी

चुनाव क्षेत्र	प्रत्याशी
दिल्ली	
बुराड़ी	कॉमरेड मैनेजर चौरसिया
मध्य प्रदेश	
सागर	कॉमरेड रामअवतार शर्मा
गोविन्दपुरा(भोपाल)	कॉमरेड केपी द्विवेदी
गुना	कॉमरेड प्रदीप आर बी
ग्वालियर	कॉमरेड रचना अग्रवाल
राजस्थान	
पिलानी	कॉमरेड सुभाषचन्द्र

नवम्बर क्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर श्रमिक संगठनों द्वारा सभा



नागपुर : लेनिन के नेतृत्व में रूस में हुई महान नवम्बर क्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर राजभाषा भवन, बर्डी नागपुर में मजदूर संगठनों द्वारा 13 नवम्बर को जाहिर सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता भारतीय कामगार सेना के नेता विजय तगलपल्लेवार ने की। सभा का आयोजन ऑल इण्डिया यूटीयूसी, खसताटी महिला कामगार संगठन, भारतीय कामगार सेना, मजदूर यूनियन, राष्ट्रीय इस्पात कामगार संगठन, संदीप गेटल क्राफ्ट कामगार संगठन, पेपर कामगार संगठन, इन्जिनियरिंग कामगार संगठन आदि की ओर से किया गया। कॉ. राजेन्द्र गंगोत्री, एआईयूटीयूसी के कॉमरेड माधव भोंडे, कॉ. आरसी राजपूत आदि वक्ताओं ने सभा को सम्बोधित किया। सभा का प्रास्ताविक कॉ. रवीन्द्र साखरे ने किया और संचालन कॉ. अशोक पवार ने किया।

कानपुर देहात बंद सफल



ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा बहु) तारा देवी के अपहरण, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या में शामिल सभी दरिन्दों को गिरफ्तार करने और फांसी की सजा दिलाये जाने, अपराधियों को बचाने व सबूतों को नष्ट होने देने में मदद करने वालों को सख्त सजा दिये जाने, सीबीआई जाँच कराये जाने, थानाध्यक्ष सिकन्द्रा को बर्खास्त करने, मृतका के आश्रितों को तत्काल सहायता के रूप में कम से कम 10 लाख रुपये और एक आश्रित को सरकारी नौकरी

देने और सभी आशा कर्मियों को सुरक्षा की गारण्टी दिये जाने की मांग पर 16 नवम्बर को कानपुर देहात बंद सफल रहा। बंद का आह्वान उ.प्र. ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा यूनियन द्वारा किया गया था। इस अवसर पर निकाले गये जुलूस का नेतृत्व यूनियन के अध्यक्ष कॉ. वालेन्द्र कटियार, महामंत्री अर्चना भोसले और कानपुर जिला देहात अध्यक्ष ममता अवस्थी ने किया।

छात्रों का धरना

महुआ (वैशाली) : जिला के बिट्टूर प्रखण्ड में गत दिनों स्कूली छात्रा से बलात्कार और छठ पर्व के खरना के दिन 11 वर्षीय छात्रा से बलात्कार और उसके कत्ल की वीभत्स वारदात के खिलाफ ऑल इण्डिया डीएसओ ने 13 नवम्बर को गांधी चौक स्मारक पर धरना-सभा की। इन बलात्कारों एवं हत्या में शामिल सभी दरिन्दों को गिरफ्तार करने और सख्त सजा दिये जाने, छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा की गारण्टी किये जाने की मांग की गई। कॉ. ललित घोष के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री



व पुलिस महानिदेशक, पटना के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

आशा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा



भिवानी (हरियाणा) : आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन 15000 रुपये मासिक देने, आदि मांगों को लेकर ऑल इण्डिया यूटीयूसी से सम्बन्धित आशा कार्यकर्ता यूनियन ने 15 नवम्बर को स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी के आवास पर प्रदर्शन किया और डीसी की मार्फत सीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व आशा कार्यकर्ता यूनियन की जिला प्रधान गुड्डी और ऑल इण्डिया यूटीयूसी के जिला कमेट्री सदस्य कॉ. राजकुमार व कॉ. धर्मवीर ने किया।